माननीय प्रधानमंत्री के 12 साल बेमिसाल : सेवा, सुशासन, जनकल्याण

व्याख्यानमाला –3

जम्मू कश्मीर की भू राजनीति एवं अनुच्छेद 370

मुख्य वक्ता

डॉ0 अमित सिंह

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

दिनांक 16 जून 2026 पुर्वाहन 11:00 बजे

कार्यक्रम संरक्षक एवं अध्यक्ष

आचार्य सत्यकाम जी

माननीय कुलपति

नोडल अधिकारी कार्यक्रम

प्रोफेसर संजय कुमार सिंह

भूगोल, समाज विज्ञान विद्याशाखा

आयोजक

उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय

प्रयागराज

Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj
12 साल बेमीसाल
12 UNPARALLELED YEARS
Trust, Development, Public Welfare
5 to 21 June 2026
Congratulations on successfully completing 12 Glorious and Unparalleled Years of Governance!
#12SaalBemisaal #ViksitBharat2047

उ.प्र. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
द्वारा आयोजित
व्याख्यानमाला
16 जून 2026 | पूर्वाह्न 11.00 बजे से
विषय: "जम्मू कश्मीर की भू-राजनीति एवम अनुच्छेद 370"
12 साल बेमीसाल
12 UNPARALLELED YEARS
विश्वास, विकास, जन कल्याण
5 से 21 जून 2026
प्रमुख वक्ता एवं पदाधिकारी
संरक्षक एवं अध्यक्ष
आचार्य सत्यकाम
माननीय कुलपति,
यू.पी.आर.टी.ओयू. प्रयागराज
मुख्य वक्ता
डॉ. अमित सिंह
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
कार्यक्रम अधिकारी (नोडल)
प्रो. संजय कुमार सिंह
भूगोल विभाग,
यू.पी.आर.टी.ओयू. प्रयागराज
धन्यवाद ज्ञापन
प्रो. आनंदानंद त्रिपाठी
राजनीति विज्ञान विभाग,
यू.पी.आर.टी.ओयू. प्रयागराज
ज़ूम मीटिंग आई. डी : 999 1423 4939
पासवर्ड: 1234
व्हाट्स ग्रुप लिंक
https://chat.whatsapp.com/Gy6k50nNVjxAlccgnyVms6
संपर्क: 7525048007
#12SaalBemisaal #ViksitBharat2047
संपर्क: 7525048007

भारत पीसेज पर नहीं, पीस पर विश्वास करता है

–आचार्य सत्यकाम जी

केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल सेवा सुशासन जन कल्याण नीति के तहत उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी के उपलब्धियो नीतियों योजनाओं कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 5 जून से 21 जून 2026 तक बौद्धिक संस्कृतिक एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। व्याख्यानमाला के तीसरे दिन के कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की भू राजनीति एवं अनुच्छेद 370 को लेकर एक ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन आज किया गया व्याख्यान के आयोजन की शुरुआत कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर संजय सिंह के वाचिक स्वागत और विषय परिवर्तन के साथ हुआ व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली थे उन्होंने जम्मू कश्मीर की भौगोलिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक आदि विभिन्न विशेषताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय दखल, ऐतिहासिक विभिन्न घटनाक्रम को अपनी व्याख्यान में शामिल करते हुए धारा 370 अनुच्छेद 35ए को हटाए जाने की विस्तृत औचित्य को रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना की और जम्मू कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए बताया कि कबायली घुसपैठ ना होकर वह कबीलाई वेश में पाकिस्तानी सेना थी जो जम्मू कश्मीर में भू क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए आगे बढ़ी क्योंकि भारतीय सेना ने इन कबायलियों के मिशन को रोका और और हरी सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से समझौता हुआ संविधान निर्माण के दौरान जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए संविधान में धारा 35ए व 370 का प्रबंध किया गया जबकि इस धारा का विरोध डॉ भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल दोनों ने किया और यह भारत की जटिल समस्या 1949 से आज तक बनी रही। इसको समाप्त करने के लिए मोदी जैसा व्यक्तित्व नहीं दिखा प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में सरकार बनते एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया और धारा 350ए व अनुच्छेद 370 को समाप्त कर एक अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर की एक संवैधानिक स्थिति बना दी गई। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पास हुआ, वहां की वाल्मीकि समाज को आरक्षण नहीं था वहां कि कोई मुस्लिम लड़की भारत के अन्य क्षेत्रों से शादी करने पर उसकी नागरिकता और जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने के अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते थे यदि वही लड़की पाकिस्तान के किसी पुरुष से शादी कर ले तो उसके समस्त अधिकार सुरक्षित रहते थे और इतना ही नहीं बल्कि उसके पति को जम्मू कश्मीर में बसने, रहने का पूरा अधिकार मिल जाता था इस कारण से वहॉ पत्थरबाज, अलगाववाद आतंकी और विरोधी गतिविधियां अन्य देश विरोधी गतिविधियों को बल मिलता था जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह चीन, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान चारों देशों के चौराहे पर है इसके साथ चीन की निगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर पड़ती रही और पाकिस्तान को मिलाकर सीधे कॉरिडोर बनाकर प्रयास करता था जिससे उसके जहाज भारत, श्रीलंका व मलाया की परिक्रमा करने में ईंधन और समय की बचत कर सके इसलिए पाकिस्तान कूटनीतिक और राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा चीन को दिया और चीन, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित करते हुए अक्साइ चीन का निर्माण कर लिया धारा 35ए व अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के लिए 2019 में अत्यंत अनुकूल परिस्थितियों बन गई पाकिस्तान तालिबान स्थित अफगानिस्तान से उलझा हुआ है और अंतरराष्ट्रीय प्रदेश पर भारत का प्रभाव भी पहले से बढ़ चुका है ऐसी स्थिति में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर कि भारत में अन्य राज्य क्षेत्र की तरह एकीकरण विकास, महिलाओं के अधिकार, राष्ट्रीय एकता, निवेश, एससी

एसटी आरक्षण, पंचायत चुनाव, रोजगार सुरक्षा व आधारभूत संरचना आदि के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए माननीय कुलपति जी ने कश्मीरियत संस्कृति जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी, व कश्मीरी सबके मिलजुल की बात करते हुए राष्ट्रीय एकता पर बल देने को कहा । माननीय कुलपति जी ने यह भी बताया कि जम्मू कश्मीर जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बल्कि वह भारतीयों का ताज है , भारत की संस्कृति पीसेज पर नहीं पीस पर विश्वास करता है । भारतीय संविधान से अलगाववाद, उग्रवाद व आतंकवाद आदि को समाप्त कर विकास की धारा में जम्मू कश्मीर को जोड़ना आवश्यक नहीं अनिवार्य अनिवार्य था। यह कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के ही बस की बात थी जिसे उन्होंने कार्य रूप में अंजाम दिया हैं।

मुक्त चिन्तन

News Letter

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत अधिनियम संख्या 10, 1999 द्वारा स्थापित

मुक्त चिन्तन 16 जून, 2026

मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यानमाला का आयोजन

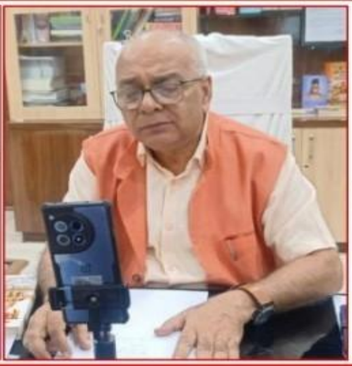

मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार दिनांक 16 जून, 2026 को जम्मू–कश्मीर की भू–राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली रहे तथा अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो0 सत्यकाम जी ने की।

प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

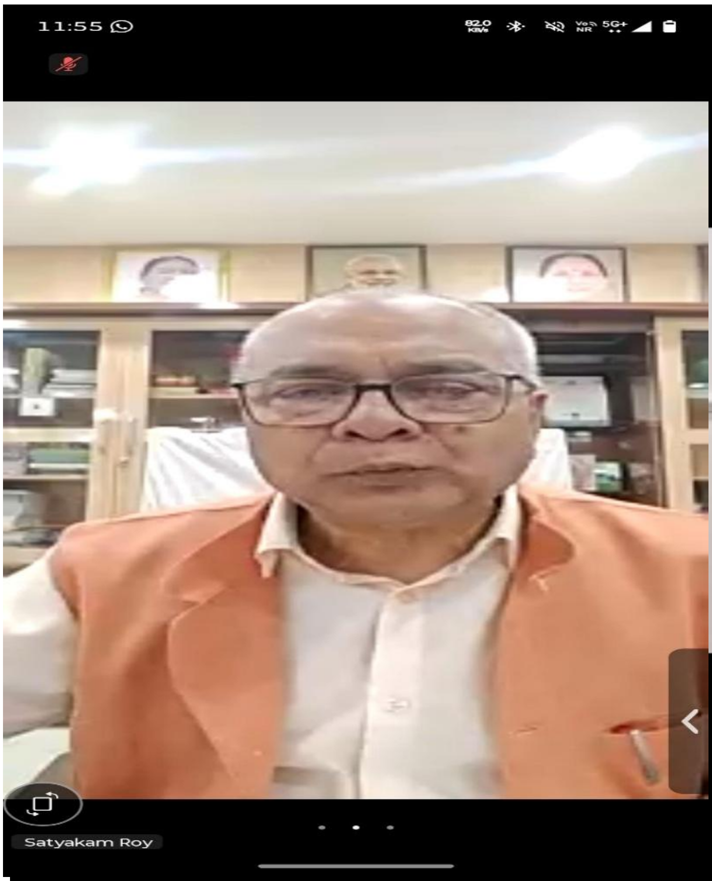
11:55
Satyakam Roy

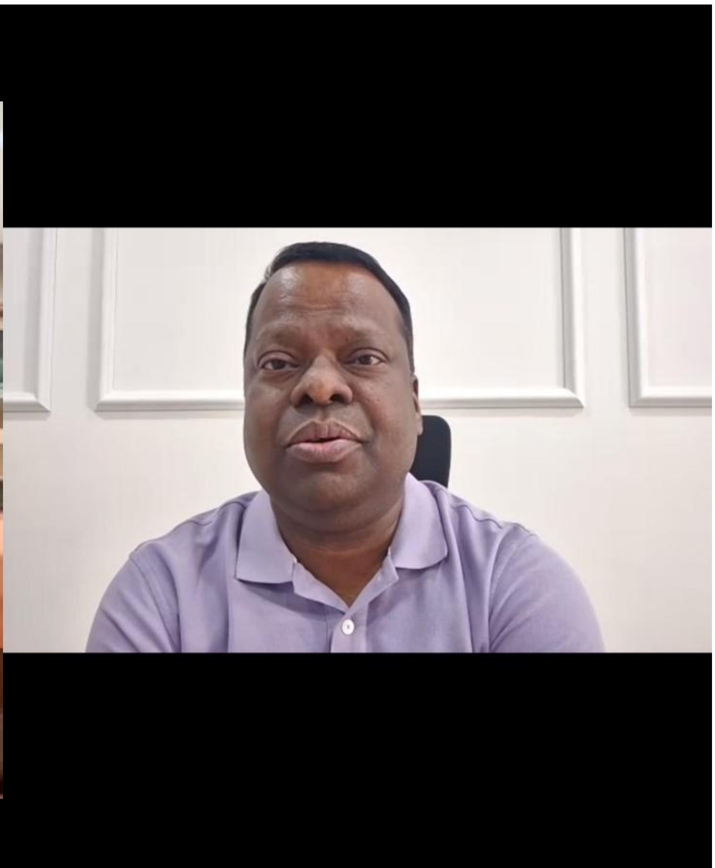

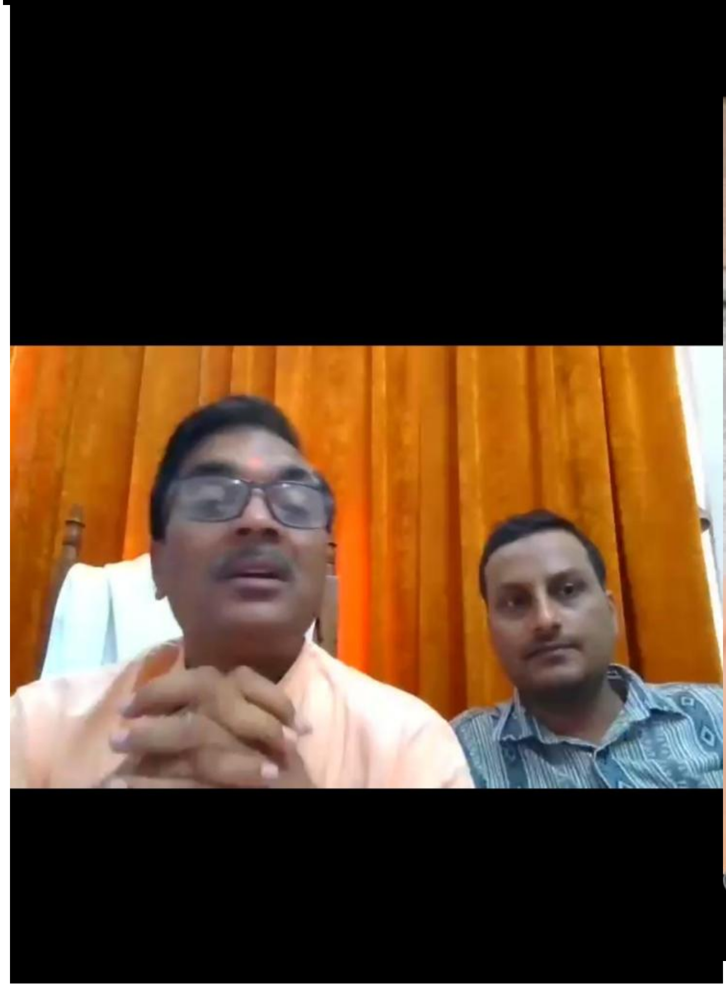

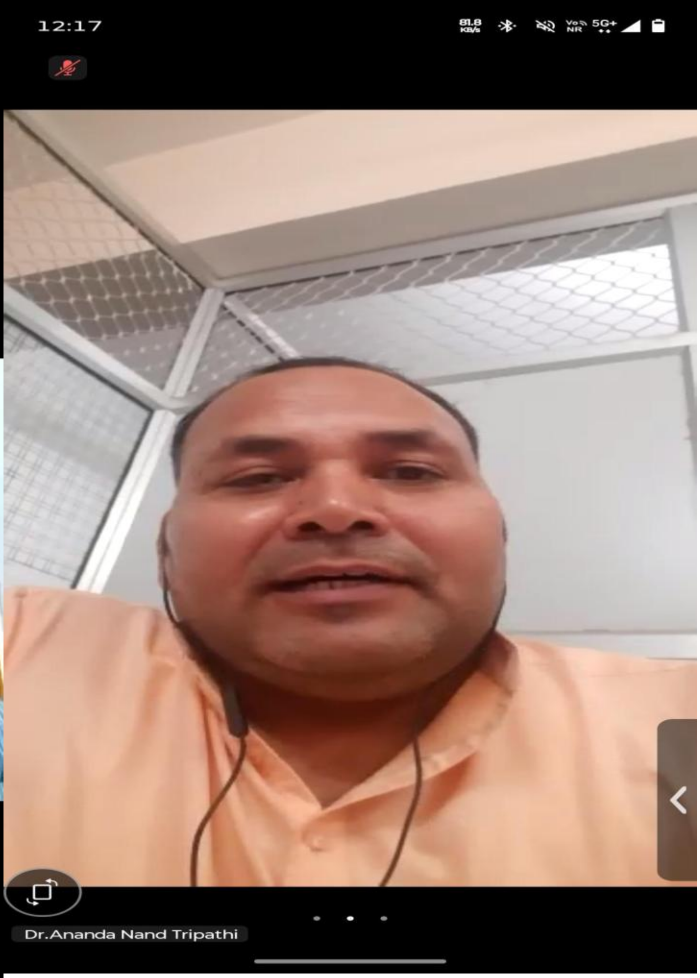
12:17
Dr.Ananda Nand Tripathi

11:21
Amit Singh
Ankit Yadav
Dr.Ananda Nand Tripathi
Dr.YOGESH KUMAR YADAV
Pro. Sanjay Singh
RC Ayodhya Ayodhya
Xiaomi 23073RPBFG
Yogesh T
Jyotiraditya Shukla

11:58
BABITA SHUKLA
Dr Sunil Kumar
Dr.Ananda Nand Tripathi
Dr.Satish Jaisal- UPRTOU
Pro. Sanjay Singh
RC Ayodhya Ayodhya
REGIONAL CENTER GORAKHPUR
Satyakam Roy
You are muted
Xiaomi 23073RPBFG
motorola moto g52

11:21
Amit Singh
Ankit Yadav
Dr.YOGESH KUMAR YADAV
Pro. Sanjay Singh
Xiaomi 23073RPBFG
Yogesh Thakur Mau
1234
Jyotiraditya Shukla

12:03
Dr.Satish Jaisal- UPRTOU
Pro. Sanjay Singh
RC Ayodhya Ayodhya
REGIONAL CENTER GORAKHPUR
Satyakam Roy
Xiaomi 23073RPBFG
You are muted

11:19
REC
Jyotiraditya Shukla
Pro. Sanjay Singh

11:19
Jyotiraditya Shukla
Sunil Kumar

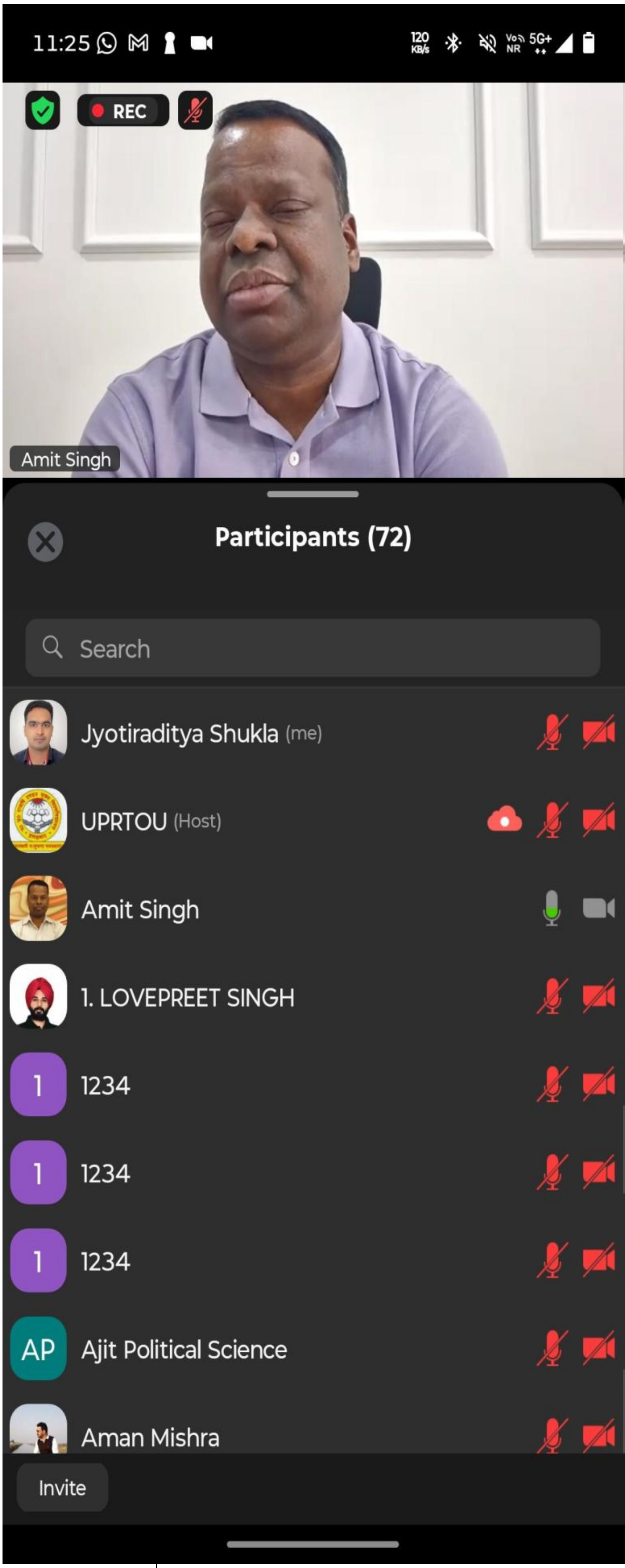
11:25
REC
Amit Singh
Participants (72)
Search
Jyotiraditya Shukla (me)
UPRTOU (Host)
Amit Singh
1. LOVEPREET SINGH
1234
1234
1234
Ajit Political Science
Aman Mishra
Invite

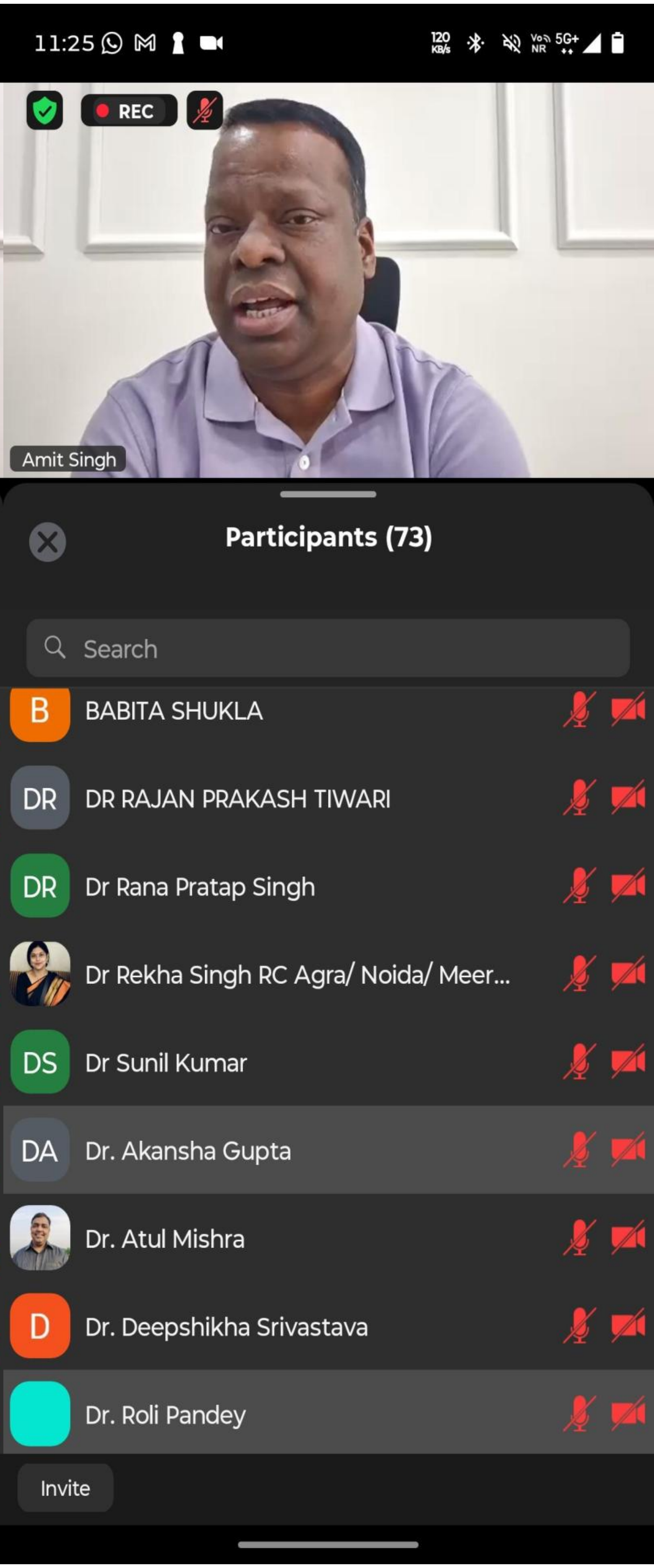
11:25
REC
Amit Singh
Participants (73)
Search
BABITA SHUKLA
DR RAJAN PRAKASH TIWARI
Dr Rana Pratap Singh
Dr Rekha Singh RC Agra/ Noida/ Meer...
Dr Sunil Kumar
Dr. Akansha Gupta
Dr. Atul Mishra
Dr. Deepshikha Srivastava
Dr. Roli Pandey
Invite

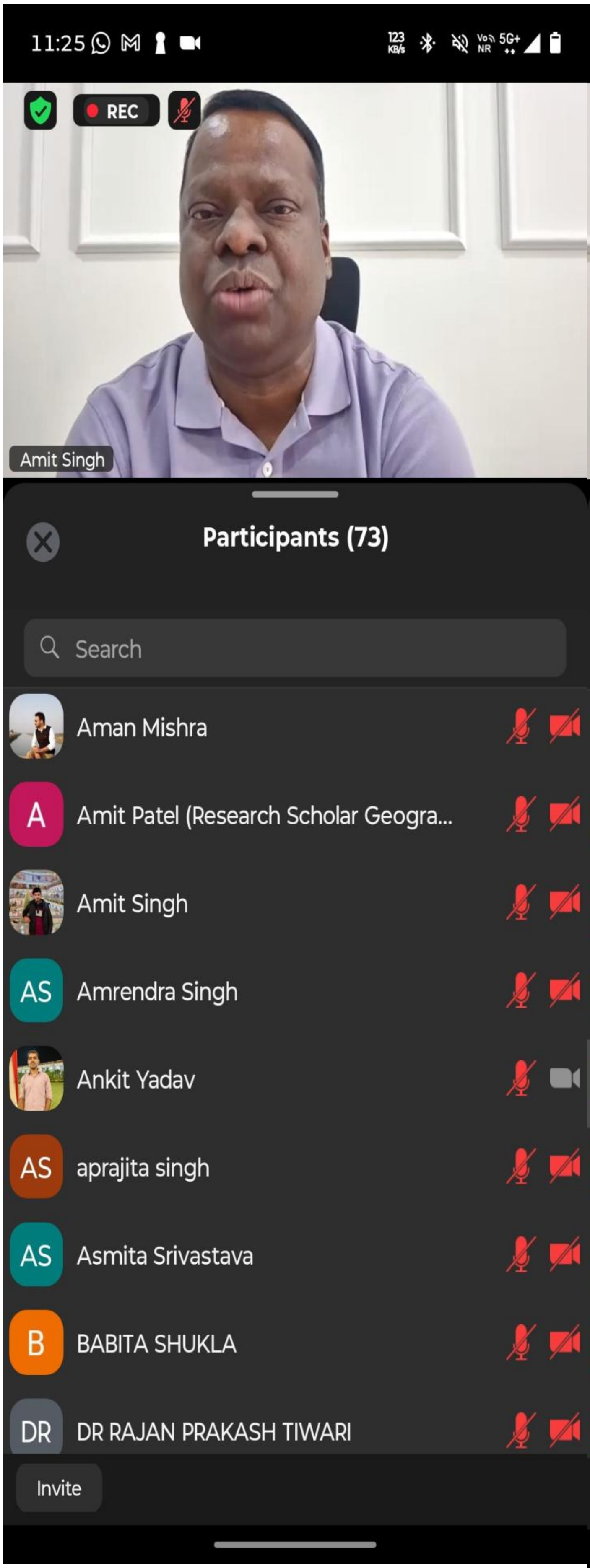
11:25
REC
Amit Singh
Participants (73)
Search
Aman Mishra
A
Amit Patel (Research Scholar Geogra...
Amit Singh
AS
Amrendra Singh
Ankit Yadav
AS
aprajita singh
AS
Asmita Srivastava
B
BABITA SHUKLA
DR
DR RAJAN PRAKASH TIWARI
Invite

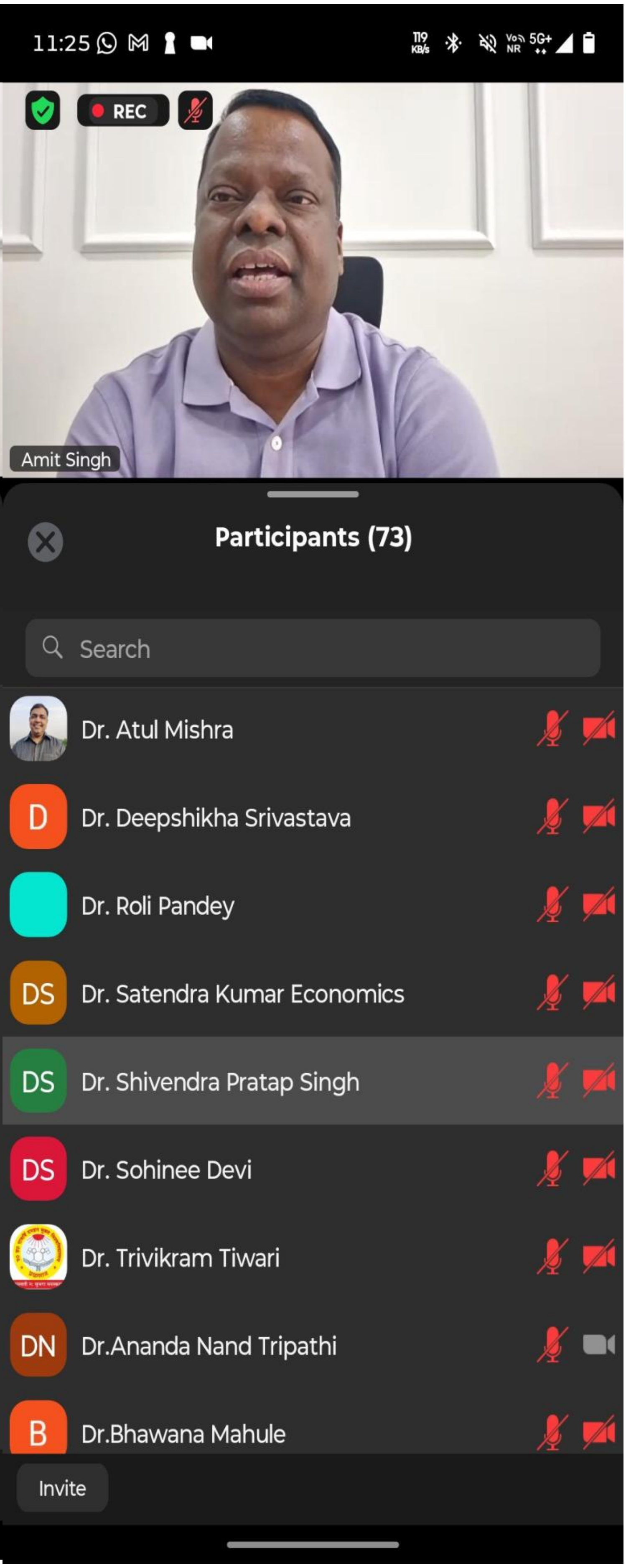
11:25
REC
Amit Singh
Participants (73)
Search
Dr. Atul Mishra
D
Dr. Deepshikha Srivastava
Dr. Roli Pandey
DS
Dr. Satendra Kumar Economics
DS
Dr. Shivendra Pratap Singh
DS
Dr. Sohinee Devi
Dr. Trivikram Tiwari
DN
Dr.Ananda Nand Tripathi
B
Dr.Bhawana Mahule
Invite

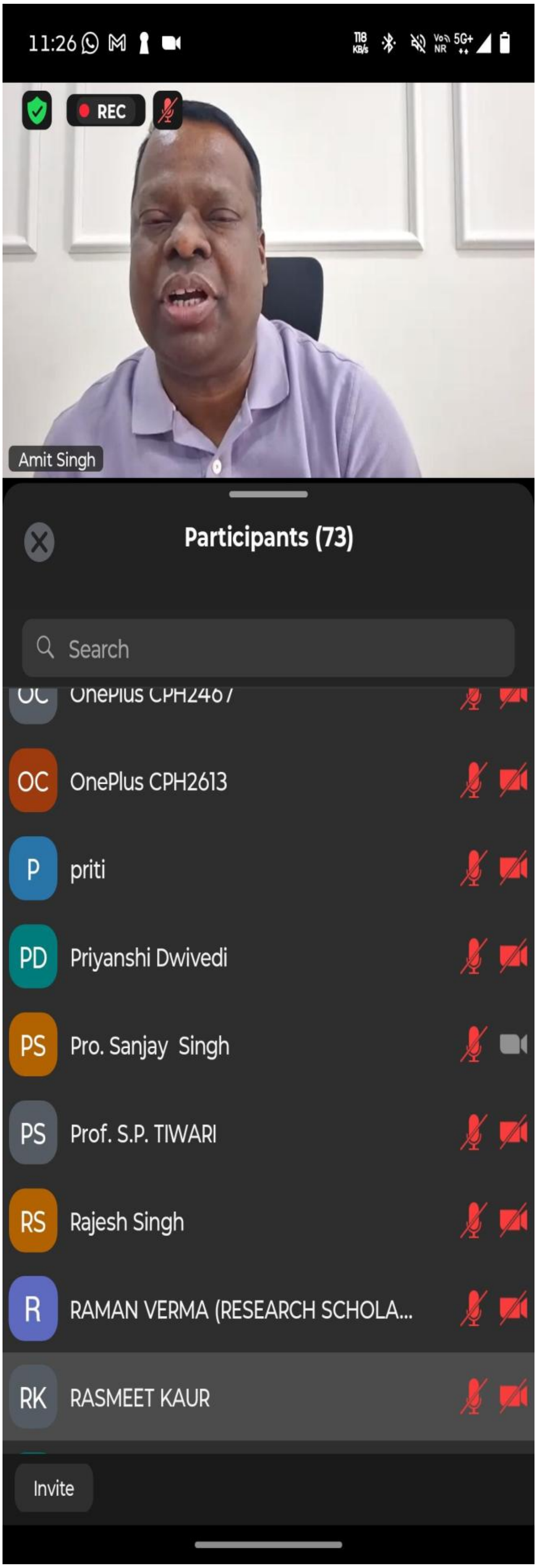
11:26
REC
Amit Singh
Participants (73)
Search
OnePlus CPH2613
priti
Priyanshi Dwivedi
Pro. Sanjay Singh
Prof. S.P. TIWARI
Rajesh Singh
RAMAN VERMA (RESEARCH SCHOLA...
RASMEET KAUR
Invite

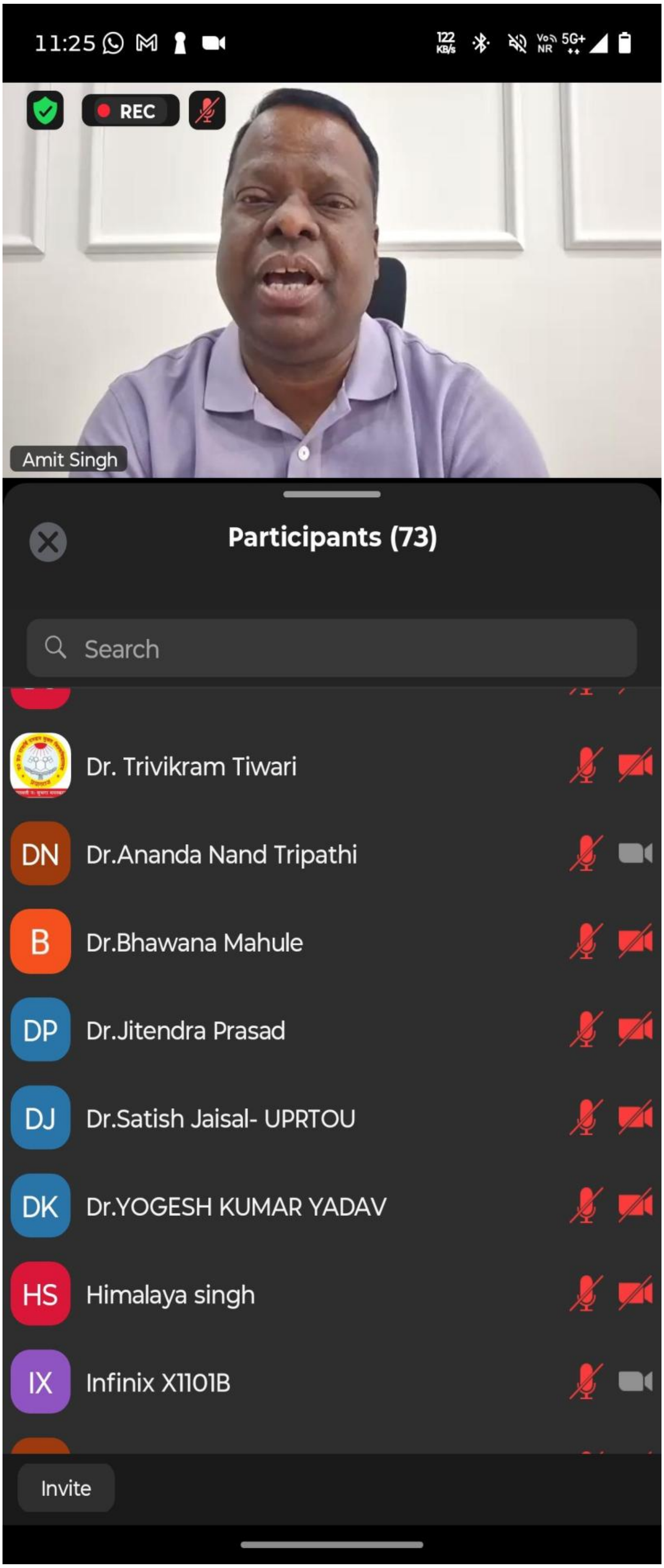
11:25
REC
Amit Singh
Participants (73)
Search
Dr. Trivikram Tiwari
Dr.Ananda Nand Tripathi
Dr.Bhawana Mahule
Dr.Jitendra Prasad
Dr.Satish Jaisal- UPRTOU
Dr.YOGESH KUMAR YADAV
Himalaya singh
Infinix X1101B
Invite

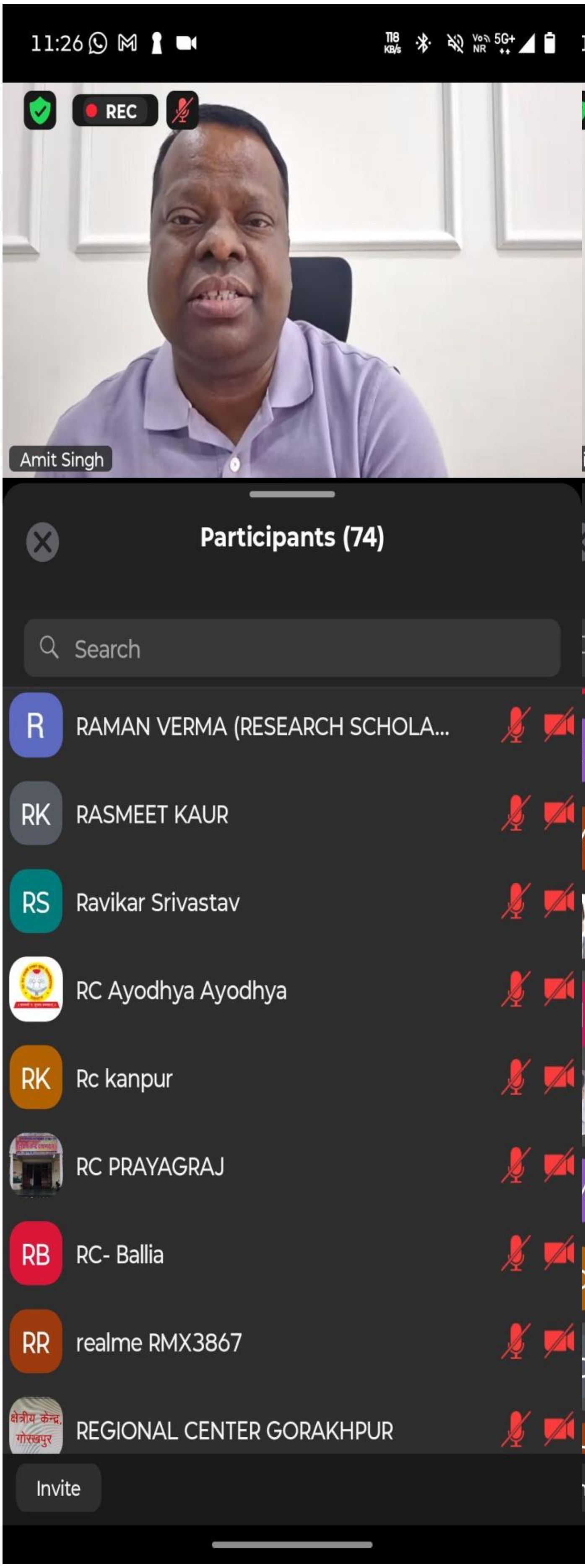
11:26
REC
Amit Singh
Participants (74)
Search
RAMAN VERMA (RESEARCH SCHOLA...
RASMEET KAUR
Ravikar Srivastav
RC Ayodhya Ayodhya
Rc kanpur
RC PRAYAGRAJ
RC- Ballia
realme RMX3867
REGIONAL CENTER GORAKHPUR
Invite

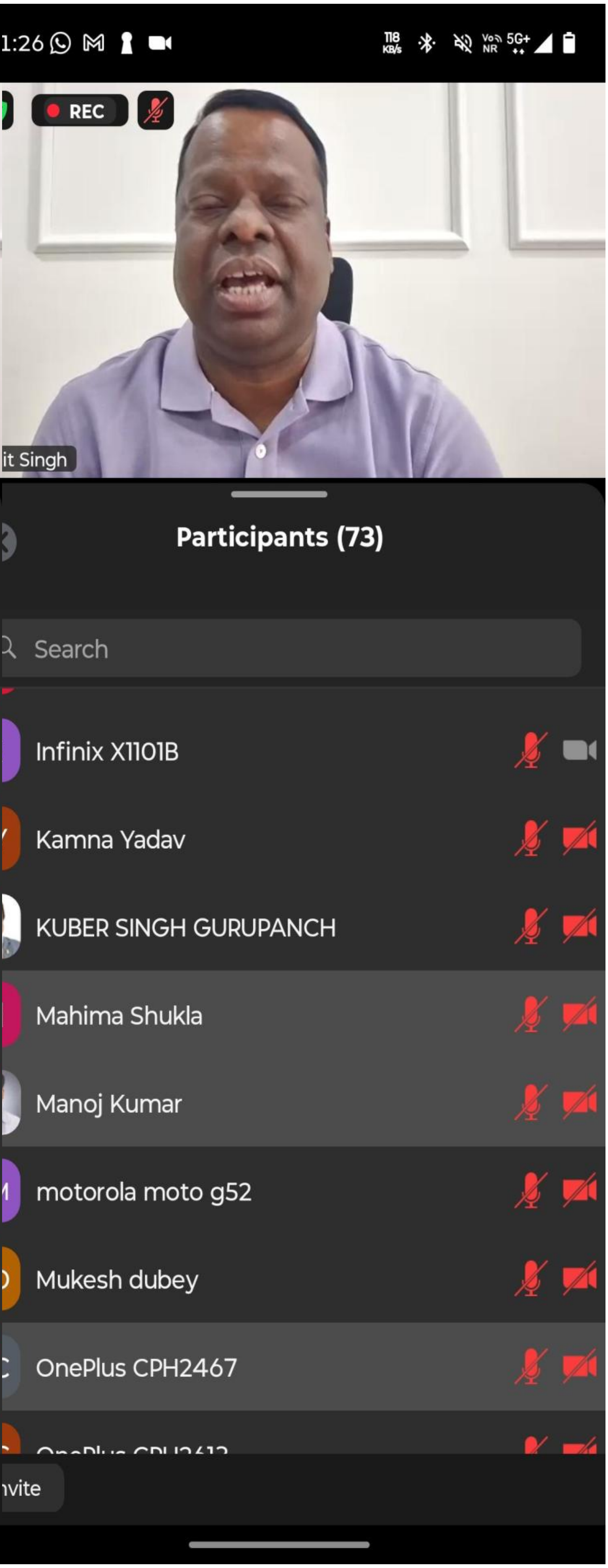
1:26
REC
it Singh
Participants (73)
Search
Infinix X1101B
Kamna Yadav
KUBER SINGH GURUPANCH
Mahima Shukla
Manoj Kumar
motorola moto g52
Mukesh dubey
OnePlus CPH2467
nvite

मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित सिंह, भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर - प्रोफेसर सत्यकाम

मंत्र भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया।

उन्होंने कहा कि समय के साथ ये प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बने रहे और इनके पक्ष-विपक्ष में विभिन्न मत सामने आते रहे। उनके अनुसार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया तथा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाते हुए राज्य को अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की भाँति संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाया गया।

प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक

संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, वाल्मीकि समाज के अधिकारों, स्थानीय स्वशासन तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के बाद सामाजिक न्याय और समान अवसरों के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों का केन्द्र रहा है। चीन-पाकिस्तान संबंधों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा अक्साई चीन जैसे मुद्दों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ाया है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाएँ भी प्रस्तुत कीं, जिनका मुख्य वक्ता ने तथ्यपरक एवं संतुलित उत्तर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व था। इस दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज जम्मू-कश्मीर शिक्षा, आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। कुलपति ने जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लें।

प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित सिंह

- भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर - प्रोफेसर सत्यकाम
- मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

संयम भारत संवाददाता

प्रयागराज, 16 जून। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है। मुख्य वक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि समय के साथ ये प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बने रहे और इनके पक्ष-विपक्ष में विभिन्न मत सामने आते रहे। उनके अनुसार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया तथा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाते हुए राज्य को अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की भाँति संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाया गया। प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, वाल्मीकि समाज के अधिकारों, स्थानीय स्वशासन तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के बाद सामाजिक न्याय और समान अवसरों के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों का केन्द्र रहा है। चीन-पाकिस्तान संबंधों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा अक्साई चीन जैसे मुद्दों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ाया है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाएँ भी प्रस्तुत कीं, जिनका मुख्य वक्ता ने तथ्यपरक एवं संतुलित उत्तर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद,

उग्रवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व था। इस दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज जम्मू-कश्मीर शिक्षा, आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। कुलपति ने जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लें। प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

मेडिकल कॉलेज के लिए गौरव का क्षण : डीएम छात्र डॉ. वागीश बरनवाल ने जीता राष्ट्रीय स्तर का "Best Case Award"

संयम भारत संवाददाता

प्रयागराज।मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के

है। इस उपलब्धि के पीछे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ शिक्षकों का मार्गदर्शन रहा। विशेष

1500 प्रतिनिधियों की उपस्थिति वाले इस राष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि हमारे छात्रों की चिकित्सकीय दक्षता,

सौंपा गया। मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान उपलब्ध कराया जाए।

मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित सिंह, भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर - प्रोफेसर सत्यकाम

प्रयाग केसरी संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया।

उन्होंने कहा कि समय के साथ ये प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बने रहे और इनके पक्ष-विपक्ष में विभिन्न मत सामने आते रहे। उनके अनुसार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया तथा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाते हुए राज्य को अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की भाँति संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाया गया।

प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक

संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, वाल्मीकि समाज के अधिकारों, स्थानीय स्वशासन तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के बाद सामाजिक न्याय और समान अवसरों के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों का केन्द्र रहा है। चीन-पाकिस्तान संबंधों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा अक्साई चीन जैसे मुद्दों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ाया है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाएँ भी प्रस्तुत कीं, जिनका मुख्य वक्ता ने तथ्यपरक एवं संतुलित उत्तर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व था। इस दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज जम्मू-कश्मीर शिक्षा, आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। कुलपति ने जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लें।

प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित सिंह, भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर - प्रोफेसर सत्यकाम

शौर्य भारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया।

उन्होंने कहा कि समय के साथ ये प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बने रहे और इनके पक्ष-विपक्ष में विभिन्न मत सामने आते रहे। उनके अनुसार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया तथा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाते हुए राज्य को अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की भाँति संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाया गया।

प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक

संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, वाल्मीकि समाज के अधिकारों, स्थानीय स्वशासन तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के बाद सामाजिक न्याय और समान अवसरों के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों का केन्द्र रहा है। चीन-पाकिस्तान संबंधों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा अक्साई चीन जैसे मुद्दों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ाया है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाएँ भी प्रस्तुत कीं, जिनका मुख्य वक्ता ने तथ्यपरक एवं संतुलित उत्तर दिया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व था। इस दिशा में उठाए गए ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज जम्मू-कश्मीर शिक्षा, आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में नई ऊँचाइयों की ओर अग्रसर है। कुलपति ने जनसमुदाय से आह्वान किया कि वे राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए एक सशक्त, समरस और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लें।

प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले- प्रो. अमित सिंह

भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर- प्रोफेसर सत्यकाम

लोकमित्र ब्यूरो

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की

भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थीं।

व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाएँ भी प्रस्तुत कीं, जिनका मुख्य वक्ता ने तथ्यपरक एवं संतुलित उत्तर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

रेलवे द्वारा विकसित अभिनव | की अवधारणा एवं उसके सफल | नवाचार में महाप्रबंधक नरेश पाल | की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह | कर सकती है। | करते हुए नोटिस बोर्ड भी लगाया।

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो अमित सिंह

➔ भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीरः प्रो सत्यकाम

➔ मुक्त विवि में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

प्रयाग भारत

प्रयागराज,। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है। जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया तथा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाते हुए राज्य को अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की भाँति संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाया गया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएं विद्यमान थीं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों का केन्द्र रहा है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परम्परा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।कुलपति ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, उग्रवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों से मुक्त कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय दायित्व था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में विकास, सुशासन और राष्ट्रीय एकीकरण की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज जम्मू-कश्मीर शिक्षा, आधारभूत संरचना, पर्यटन, निवेश और जनकल्याण के क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है।

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित सिंह

तिजारत संवाददाता

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जेएनयू प्रो अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। प्रो अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। कुलपति प्रो सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है।

फ्लिपकार्ट, रिलाइंस, भारत मोटर्स, लावा के साथ प्रतिभाग कर सकते है। और उसके त्वरित निस्तारण की इस जा सका।

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित सिंह

भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर - प्रोफेसर सत्यकाम, मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया।इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान

समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया।उन्होंने कहा कि समय के साथ ये प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बने रहे और इनके पक्ष-विपक्ष में विभिन्न मत सामने आते रहे। प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थीं। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। । कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है।प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

Jammu & Kashmir's Full Integration Has Opened New Doors for Development: Prof. Amit Singh

Jammu & Kashmir is the Crown of India's Identity and Pride: Prof. Satyakam

JE CORRESPONDENT

Prayagraj, June 16: As part of the lecture series organized to mark the completion of 12 years of the Central Government, an online lecture on "The Geopolitics of Jammu & Kashmir and Article 370" was held on Tuesday at Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj.

On this occasion, the keynote speaker, Prof. Amit Singh, Centre for National Security Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, presented a detailed analysis of the geographical, economic, social, cultural, and political distinctiveness of Jammu & Kashmir. He stated that Jammu & Kashmir is not merely a border region but an extremely significant entity from India's strategic, cultural, and political perspectives, whose position has directly influenced the geopolitics of South Asia.

The keynote speaker observed that following the full integration of Jammu & Kashmir, new opportunities have emerged in the fields of development, investment, infrastructure, empowerment of Panchayati Raj institutions, employment generation, education, women's rights, and social justice. He urged the youth to prioritize national interest, constitutional values, and the spirit of national unity while actively contributing to India's overall development.

Prof. Amit Singh referred to the historical developments in Jammu & Kashmir and stated that the

so-called tribal invasion of 1947 was, in reality, a Pakistan-backed military operation carried out under the guise of tribal forces, which was courageously countered by the Indian Army. He explained that, under the circumstances prevailing at the time, Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession with India. During the constitution-making process, Articles 370 and 35A were incorporated in view of the special circumstances of Jammu & Kashmir.

He noted that over time these provisions remained an important subject of national debate, attracting diverse opinions both in support and opposition. According to him, in 2019, under the leadership of Prime Minister Narendra Damodardas Modi, the Central Government implemented the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, rendering most provisions of Article 370 inoperative and bringing the region within the constitutional framework applicable to other states and Union Territories.

Prof. Amit Singh stated that the earlier arrangement had given rise to several constitutional and social complexities. Referring to issues related to women's rights, reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the rights of the Valmiki community, local self-governance, and implementation of development schemes, he said that the new framework has expanded opportunities for social justice and equal access.

dation Officer reserved the land Mishra, usurped his land by should be provided while pro- action. workforce needs. CTS contin- nance and industry linkages.

Complete integration of J&K has opened doors to development: Prof. Amit Singh

Jammu and Kashmir crown of Indian identity and pride: Prof Satyakam

OPEN UNIV ORGANIZES LECTURE SERIES ON 12 YEARS OF EXCELLENCE

SANYAM BHARAT CORRESPONDENT

Prayagraj: On the third day of the lecture series organised to mark the completion of 12 years of the Central Government at Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj, an online lecture was organised on the topic of geopolitics of Jammu and Kashmir and Article 370 on Tuesday.

On this occasion, the keynote speaker, Professor Amit Singh, Centre for National Security Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, presented a detailed analysis of the geographical, economic, social, cultural, and political characteristics of Jammu and Kashmir. He stated that Jammu and Kashmir is not merely a border state, but a strategically, culturally, and politically significant entity within India, whose position directly influences the geopolitics of South Asia.

The keynote speaker stated that the full integration of Jammu and Kashmir has opened new possibilities in the areas of development, investment, infrastructure, panchayat empowerment, employment generation, education, women's rights, and social justice. He called upon the youth to ensure their active participation in India's overall development, while prioritizing national interest, constitutional values, and the spirit of national unity.

Referring to the historical events in Jammu and Kashmir, Professor Amit Singh said that the so-called tribal incursion of 1947 was actually a Pakistan-backed military action disguised as tribal garb, which the Indian Army courageously countered. He explained that under the prevailing circumstances, Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession with India, and during the Constitution-making process, provisions for Article 370 and Article 35A were enacted, taking into account the special circumstances of Jammu and Kashmir.

He said that over time, these provisions remained a significant topic of national debate, and various opinions emerged for and against them. According to him, in 2019, as a result of a decision taken by the central government under the leadership of Prime Minister Narendra Damodardas Modi, the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 was implemented, nullifying most of the provisions of Article 370 and bringing the state within the ambit of the constitutional system like other states and union territories.

Professor Amit Singh stated that the previous system had created numerous constitutional and social complexities. He highlighted various aspects related to women's rights, reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the rights of the Valmiki community, local self-governance, and the implementation of development plans. He stated that the new system has increased the potential for expanding social justice and equal opportunities. Referring to the strategic location of Jammu and Kashmir, he said that the region has been at the center of complex geopolitical situations involving India, Pakistan, and China. Issues such as China-Pakistan relations, Pakistan-occupied Kashmir, and Aksai Chin

have further enhanced the region's strategic importance. India's growing global reputation and diplomatic strength in the changing international landscape also played a significant role in creating favorable conditions for this decision. During the lecture, participants also presented various queries related to the topic, to which the keynote speaker provided factual and balanced answers.

Presiding over the event, Professor Satyakam, Vice Chancellor of Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj, in his address, highlighted the rich Kashmiriyat culture of Jammu and Kashmir, highlighting the spirit of national unity, integrity, and cultural integration. He said that Kashmiriyat is not merely a geographical identity, but a symbol of the cultural consciousness developed over centuries, in which Hindu, Muslim, Dogra, Ladakhi, and Kashmiri communities have lived together in harmony, coexistence, and brotherhood. This tradition of unity in diversity is India's greatest strength.

Vice Chancellor Professor Satyakam said that Jammu and Kashmir is not just a piece of Indian territory, but a crown of Indian identity and pride. India's culture does not believe in division, but in the values of peace, dialogue, coexistence, and humanity. He said that the fundamental spirit of Indian democracy and the Constitution is to provide equal opportunities, justice, and development to all citizens.

He stated that freeing Jammu and Kashmir from challenges like separatism, extremism, and terrorism and integrating it into the mainstream of development was not merely an administrative necessity but a national responsibility. Referring to the historic steps taken in this direction, he said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, new possibilities for development, good governance, and national integration have been paved in Jammu and Kashmir. Today, Jammu and Kashmir is progressing to new heights in the areas of education, infrastructure, tourism, investment, and public welfare. The Vice Chancellor called upon the public to ensure their active participation in building a strong, harmonious, and developed India, keeping national interest paramount, and to resolve to spread the values of national unity and integrity to every citizen.

Initially, the program's nodal officer, Professor Sanjay Singh, offered a verbal welcome and introduced the topic. He highlighted the contemporary relevance of the lecture's topic. University faculty, officers, staff, researchers, and students participated in the program online.

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण से विकास के नए अवसर खुले

प्रयागराज, कार्यालय संवाददाता। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को 'जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370' विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान हुआ। मुख्य वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केंद्र के प्रो. अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विशिष्टताओं पर विस्तार से चर्चा की। प्रो. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रभावित करती रही है। कहा कि पूर्ण एकीकरण के बाद प्रदेश में विकास, निवेश, आधारभूत ढांचे, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार, शिक्षा, महिला अधिकार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। कुलपति प्रो. सत्यकाम ने भी विचार रखे।

HIND MATA — CITY

Jammu & Kashmir's Full Integration Has Opened New Doors for Development: Prof. Amit Singh

Jammu & Kashmir is the Crown of India's Identity and Pride: Prof. Satyakam

HIND MATA

Prayagraj, June 16: As part of the lecture series organized to mark the completion of 12 years of the Central Government, an online lecture on "The Geopolitics of Jammu & Kashmir and Article 370" was held on Tuesday at Uttar Pradesh Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj.

On this occasion, the keynote speaker, Prof. Amit Singh, Centre for National Security Studies, Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, presented a detailed analysis of the geographical, economic, social, cultural, and political distinctiveness of Jammu & Kashmir. He stated that Jammu & Kashmir is not merely a border region but an extremely significant entity from India's strategic, cultural, and political perspectives, whose position has directly influenced the geopolitics of South Asia.

The keynote speaker observed that following the full integration of Jammu & Kashmir, new opportunities have emerged in the fields of development, investment, infrastructure, empowerment of Panchayati Raj institutions, employment generation, education, women's rights, and social justice. He urged the youth to prioritize national interest, constitutional values, and the spirit of national unity while actively contributing to India's overall development.

Prof. Amit Singh referred to the historical developments in Jammu & Kashmir and stated that the so-called tribal invasion of 1947 was, in reality, a Pakistan-backed military operation carried out under the guise of tribal forces, which was courageously countered by the Indian Army. He explained that, under the circumstances prevailing at the time, Maharaja Hari Singh signed the Instrument of Accession with India. During the constitution-making process, Articles 370 and 35A were incorporated in view of the special circumstances of Jammu & Kashmir.

He noted that over time these provisions remained an important subject of national debate, attracting diverse opinions both in support and opposition. According to him, in 2019, under the leadership of Prime Minister Narendra Damodardas Modi, the Central Government implemented the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019, rendering most provisions of Article 370 inoperative and bringing the region within the constitutional framework applicable to other states and Union Territories.

Prof. Amit Singh stated that the earlier arrangement had given rise to several constitutional and social complexities. Referring to issues related to women's rights, reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the rights of the Valmiki community, local self-governance, and implementation of development schemes, he said that the new framework has expanded opportunities for social justice and equal access.

जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण ने विकास के द्वार खोले : प्रो. अमित

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित व्याख्यानमाला श्रृंखला के तीसरे दिन मंगलवार को जम्मू-कश्मीर की भू-राजनीति एवं अनुच्छेद 370 विषय पर ऑनलाइन व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर

▫ भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है जम्मू कश्मीर - प्रोफेसर सत्यकाम ▫ मुक्त विश्वविद्यालय में 12 साल बेमिसाल पर व्याख्यान माला का आयोजन

अमित सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन केन्द्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ने जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विशिष्टताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर केवल एक सीमावर्ती प्रदेश नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है, जिसकी स्थिति दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती रही है।

मुख्य वक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के बाद विकास, निवेश, आधारभूत संरचना, पंचायत सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रहित, संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

प्रोफेसर अमित सिंह ने जम्मू-कश्मीर के ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1947 में हुई तथाकथित कबायली घुसपैठ वस्तुतः कबायली वेश में पाकिस्तान समर्थित सैन्य कार्रवाई थी, जिसका भारतीय सेना ने साहसपूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने बताया कि तत्पश्चात तत्कालीन परिस्थितियों में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान जम्मू-कश्मीर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 370 तथा अनुच्छेद 35ए का प्रावधान किया गया।

उन्होंने कहा कि समय के साथ ये प्रावधान राष्ट्रीय विमर्श का महत्वपूर्ण विषय बने रहे और इनके पक्ष-विपक्ष में विभिन्न मत सामने आते रहे। उनके अनुसार वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 लागू किया गया तथा अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी बनाते हुए राज्य को अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की भाँति संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाया गया।

प्रोफेसर अमित सिंह ने कहा कि पूर्ववर्ती व्यवस्था के कारण अनेक संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताएँ विद्यमान थी। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, वाल्मीकि समाज के

अधिकारों, स्थानीय स्वशासन तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नई व्यवस्था के बाद सामाजिक न्याय और समान अवसरों के विस्तार की संभावनाएँ बढ़ी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की सामरिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत, पाकिस्तान और चीन से जुड़ी जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों का केन्द्र रहा है। चीन-पाकिस्तान संबंधों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तथा अक्साई चीन जैसे मुद्दों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को और अधिक बढ़ाया है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और कूटनीतिक सशक्तता ने भी इस निर्णय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों ने विषय से संबंधित विभिन्न जिज्ञासाएँ भी प्रस्तुत कीं, जिनका मुख्य वक्ता ने तथ्यपरक एवं संतुलित उत्तर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने अपने उद्बोधन में जम्मू-कश्मीर की समृद्ध कश्मीरियत संस्कृति का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं सांस्कृतिक समन्वय की भावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीरियत केवल एक भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि सदियों से विकसित उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, डोगरा, लद्दाखी और कश्मीरी समाज परस्पर सद्भाव, सहअस्तित्व और भाईचारे के साथ जीवनयापन करते आए हैं। भारत की विविधता में एकता की यह परंपरा हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।

कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत की भूमि का मात्र एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय अस्मिता और गौरव का मुकुट है। भारत की संस्कृति विभाजन नहीं, बल्कि शांति, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता के मूल्यों में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना सभी नागरिकों को समान अवसर, न्याय और विकास प्रदान करने की है। प्रारंभ में कार्यक्रम के नोडल अधिकारी प्रोफेसर संजय सिंह ने वाचिक स्वागत एवं विषय प्रवर्तन किया। उन्होंने व्याख्यान के विषय की समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों ने ऑनलाइन माध्यम से सहभागिता की।

मण्डल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन 19 जून को आई0टी0आई0 नैनी मे

प्रयागराज। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन, राजकीय आई0टी0आई0 एवं क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 19 जून, 2026 को राजकीय आई0टी0आई0 नैनी, प्रयागराज में प्रातः 10:00 बजे से एक दिवसीय मण्डल स्तरीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त मेले में निजी क्षेत्र की कम्पनी टाटा मोटर्स, फ्लिपकार्ट, रिलाइंस, भारत